दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

दिसंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **5**

- हरियाणा के नए मुख्य सचिव तथा नए वित्त आयुक्त नियुक्त 5
- तीसरी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा नंबर वन 5
- सिविल अस्पताल जगाधरी में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन 6
- मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन 6
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य के दिव्यांगजनों के लिये विभिन्न घोषणाएँ 7
- करनाल में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 4 परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास 7
- हिसार ज़िले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास 8
- मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप 9
- खेलो इंडिया प्रतियोगिता 9

नोट :

- टैब वितरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत 9
- एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट 10
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 10
- हरियाणा में स्कूल फीस वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी 10
- 'कचरे से कंचन'के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास 12
- 9वीं जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 12
- मिस यूनिवर्स -2021 13
- लीड्स रिपोर्ट: हरियाणा ने हासिल किया दूसरा स्थान 13
- कृषि-उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार-2021 14
- 1 जनवरी से हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिये नो एंट्री 14
- एचपीएससी, एचएसएससी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का निर्णय वापस लिया गया 15
- फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' हरियाणा में लॉन्च 15

नोट :

- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम पोर्टल लॉन्च 16
- सुशासन सूचकांक, 2021 में हरियाणा 16
- मुख्यमंत्री ने किया एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन 17
- अंबाला के नग्गल में होगी उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की ब्रांच की स्थापना 18
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में हरियाणा 18
- कृषि विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग में एचएयू लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम 19
- मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया नववर्ष का तोहफा 19

The Vision

नोट :

हरियाणा

हरियाणा के नए मुख्य सचिव तथा नए वित्त आयुक्त नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

- 30 नवंबर, 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कौशल को राज्य के नए मुख्य सचिव तथा एक अन्य सीनियर अधिकारी पी.के. दास को नया वित्त आयुक्त बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के निवर्तमान मुख्य सचिव विजयवर्धन के सेवानिवृत्त होने की वजह से हरियाणा के 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव कौशल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है।
- संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की सरकार के पाँचवें मुख्य सचिव होंगे।
- संजीव कौशल को राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य मामले, विजिलेंस, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा योजना समन्वय विभागों की भी ज़िम्मेदारी सौंपी है।
- हरियाणा के 1985 बैच के ही एक दूसरे सीनियर अधिकारी पी.के. दास को नया वित्त आयुक्त एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है।
- पी.के. दास को चकबंदी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- उल्लेखनीय है कि अभी तक संजीव कौशल राज्य के वित्त आयुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पी.के. दास बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे।

तीसरी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

- 27-30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित तीसरी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के साथ हरियाणा की टीम पहले स्थान पर रही।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा से इस प्रतियोगिता में 228 पुरुष और 46 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा की टीम का नेतृत्व मास्टर्स एथलीट एसोसिएशन महासचिव महावीर तालियान ने किया।
- इस प्रतियोगिता में करनाल से 23 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 20 खिलाड़ियों ने कुल 32 मेडल जीते, जिनमें से 9 गोल्ड, 11 सिल्वर तथा, 12 ब्रॉन्ज हैं।
- विजेता खिलाड़ियों में 85 प्लस आयुवर्ग में धर्मचंद घोघड़ीपुर ने 3 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल हासिल किये। इसी तरह 70 प्लस आयुवर्ग में ओमप्रकाश ने गोल्ड व सिल्वर, 68 प्लस आयुवर्ग में महावीर तालियान ने सिल्वर व ब्रॉन्ज, 65 प्लस आयुवर्ग में जोगिंद्र सिंह ने सिल्वर, 60 प्लस आयुवर्ग में श्याम सिंह नरवाल ने गोल्ड, 55 प्लस आयुवर्ग मुकाबलों में महाबीर सिंह ने ब्रॉन्ज, 50 प्लस आयुवर्ग में सलिंद्र सिंह ने सिल्वर, जितेंद्र सिंह कमांडो ने ब्रॉन्ज, राजेश कुमार खन्ना ने सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।

नोट :

- 50 प्लस आयुवर्ग में सतीश राणा ने ब्रॉन्ज मेडल, 45 प्लस में कश्मीर सिंह ने सिल्वर, 40 प्लस में भोलाराम ने ब्रॉन्ज व सिल्वर, प्रमोद कुमार पीटीआइ ने सिल्वर, अमित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं 40 प्लस आयुवर्ग में राजेश कुमारी ने गोल्ड, यशवंती ने सिल्वर, संगीता ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ममता देवी ने दो ब्रॉन्ज और रेणु ने गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ज़िले की शान बढ़ाई है।
- इस चैंपियनशिप में दादरी ज़िले के खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा। इस राष्ट्रीय स्पर्धा में कई खेलों में दादरी ज़िले से 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें इन खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 3 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं।

सिविल अस्पताल जगाधरी में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने राज्य के यमुनानगर ज़िले के जगाधरी सिविल अस्पताल में लगभग एक करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि एक हज़ार लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता वाला यह प्लांट एचडीएफसी बैंक ने बनवाया है।
- इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से नागरिक अस्पताल की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होगी।
- शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर ज़िले के अस्पतालों में इसी तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं।
- ज़िला यमुनानगर में 3500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनमें से एक-एक हज़ार लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन प्लांट- सिविल अस्पताल यमुनानगर, ईएसआई अस्पताल जगाधरी व सिविल अस्पताल जगाधरी के प्रांगण में तथा 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट सीएचसी सरस्वती नगर में लगाया गया है।

मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने साहसिक खेलों और संबद्ध पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिये फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के नाम पर 'मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब' का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- क्लब की स्थापना मौजूदा हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स (एक पंजीकृत सोसायटी) के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में साहसिक खेलों को शुरू करने, बढ़ावा देने और विकसित करने के साथ-साथ साहसिक खेलों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण तथा गुणवत्ता के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने जून में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर एक क्लब बनाने की घोषणा की थी।
- हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के विभाग के प्रधान सचिव ए.के. सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल एवं युवा मामलों के मंत्री क्लब की प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे। राज्य में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु 11 सदस्यीय समिति में पर्यटन, वन और वन्यजीव विभाग, नागरिक उडन्यन विभाग के प्रशासनिक सचिव भी होंगे।
- क्लब को ग्राउंड स्पोर्ट्स, एयरो स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स सहित साहसिक खेलों में प्रशिक्षण, कोचिंग और भ्रमण पर्यटन आयोजित करने तथा पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, स्नो स्कीइंग, साइकिलिंग में साहसिक खेल प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण करने का काम सौंपा गया है।

नोट :

- यह क्लब साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्रों, अकादमियों, उपग्रह केंद्रों, आधार शिविरों आदि की स्थापना करेगा और देश एवं विदेश में ऐसे संस्थानों के साथ समन्वय करेगा तथा ऐसे अन्य संगठनों के बीच नेशनल एडवेंचर क्लब (इंडिया), इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के साथ सहयोग करेगा।
- इसके अलावा, क्लब साहसिक खेलों में उत्कृष्टता के लिये अग्रिम प्रशिक्षण में व्यक्तियों की सहायता करने हेतु फेलोशिप भी प्रदान करेगा और निजी क्षेत्र को ऐसी सुविधाओं के विकास में वित्तीय योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करेगा। अधिसूचना के अनुसार यह एडवेंचर स्पोर्ट्स कोचिंग, वाटर स्पोर्ट्स में लाइफगार्ड, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर सामान्य रोज़गार के अवसरों तक में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य के दिव्यांगजनों के लिये विभिन्न घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

- 3 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के लिये विभिन्न घोषणाओं के साथ राज्य के हर ज़िले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में करीब 50 लाख मानसिक अक्षम लोग हैं, हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के लिये ज़्यादा-से-ज़्यादा व्यापक स्तर पर सुविधाएँ देने के प्रयास कर रही है।
- इसी प्रयास में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास किया गया।
- इसके साथ-साथ उन्होंने विशेषत: दिव्यांगजनों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवॉर्ड के लिये ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल भी लॉन्च किया।
- मुख्यमंत्री ने राजकीय अंध विद्यालय, पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिये जाने की भी घोषणा की।
- उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल के लिये अंबाला में 5 एकड़ भूमि पर 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण किया जाएगा। इसमें 100 दिव्यांगजनों के लिये वस्त्र, भोजन व उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था होगी।
- अब दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबलिटीज़ पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल पर ही अपनी शिकायत को ट्रैक करने के साथ-साथ अधिनियम सूचना, विभाग की योजनाएँ व मामला सूची विधि व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिये अवार्ड पोर्टल की शुरुआत भी की। इस पोर्टल पर दिव्यांगजन सीधे अलग-अलग श्रेणी के अवार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रेणी-1 एवं 2 के नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर देने की घोषणा की।

करनाल में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 4 परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 5 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के करनाल ज़िले में विकास से जुड़ी करीब 190 करोड़ रुपए की 9 भिन्न-भिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- करनाल में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनमें से एक 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नगर निगम का नया भवन और इसी भवन के दूसरे तल पर 153 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र है।
- अन्य परियोजनाओं में करनाल स्मार्ट सिटी के पार्कों में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया गया।
- इसी प्रकार सेक्टर-6, 13 व 14 में 2 करोड़ 34 लाख रुपए ग्रीन बेल्ट पार्कों का शिलान्यास किया गया।

नोट :

- नमस्ते चौक से मीरा घाटी चौक तक 4 करोड़ 83 लाख रुपए की विकास एवं सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास व 4 करोड़ 86 लाख रुपए से हांसी चौक से लेकर नमस्ते चौक तक सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया।
- करनाल में रामनगर व बूढ़ा खेड़ा में 71 लाख 23 हज़ार रुपए की लागत से बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा नीलोखेड़ी के सामान्य अस्पताल में 250 लीटर प्रति मिनट क्षमता तथा घरौंडा की सी.एच.सी. में 600 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया गया।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि तीसरी आँख के इस प्रोजेक्ट से शहर की सुरक्षा, निगरानी और यातायात व्यवस्थित रहेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी। आई.सी.सी.सी. 24 घंटे काम करेगा।
- उल्लेखनीय है कि ए.टी.सी.एस. के तहत 105 थर्मल कैमरे, आई.टी.एम.एस. में 35 चौराहों पर 211 कैमरे, 10 स्थानों पर स्पीड वायलेशन कैमरे, 300 से अधिक सी.सी.टी.वी. कैमरे, 35 वेरिएबल मैसेज़ बोर्ड तथा 2 जगहों पर एनवायरनमेंट सेंसर लगाए गए हैं।

हिसार ज़िले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 5 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार ज़िले से संबंधित 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न सड़कों का निर्माण, तालाबों का सुधारीकरण, भवन निर्माण, गलियों का निर्माण तथा गांव ढंढूर स्थित 16,632 एमटी गोदाम एवं कार्यालय का उद्घाटन किया गया है।
- उप-मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के आवागमन की बेहतर सुविधा के लिये 50 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विभिन्न 20 संपर्क सड़कों का उद्घाटन किया।
- इसके अतिरिक्त 271 किमी. लंबी 33 अन्य सड़कों के सुधारीकरण के कार्य का भी शुभारंभ किया, जिस पर 206 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।
- उन्होंने 19 करोड़ रुपए की लागत से तीन भवनों के निर्माण कार्य, ग्रामीण क्षेत्र के लिये 126.12 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 26 ग्रामीण ज्ञान केंद्र, 35 आँगनबाड़ी केंद्र, 10 ग्राम सचिवालय, 47 गलियों का निर्माण तथा 15 विभिन्न विकास कार्यों की मरम्मत संबंधी कार्यो का उद्घाटन किया।
- उप-मुख्यमंत्री ने हिसार के दक्षिणी पेरिफेरल रोड पर सातरोड गांव के समीप बालसंमद डिस्ट्रीब्यूट्री के साथ रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया। इसके निर्माण कार्य पर 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- उन्होंने हिसार हवाई अड्डे पर फेज-3 में कई कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें बुर्जस तथा बार्बेड वायर फेंसिंग कार्य शामिल हैं। इन कार्यों पर 285.89 लाख रुपए की लागत आएगी।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने बरवाला में 948.51 लाख रुपए तथा हांसी में 629.91 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नए विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएँ बेहतर बनाने के लिये उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार-मंगाली-स्याहड़वा तथा अग्रोहा-आदमपुर रोड के फॉरलेनिंग कार्य का शिलान्यास किया।
- इनके अलावा हिसार-खानक रोड, लक्ष्मीबाई चौक से मलिक चौक, हिसार से रायपुर रोडके फॉरलेनिंग कार्य का उद्घाटन किया।
- इस प्रकार हिसार ज़िले में कुल मिलाकर 90 किमी. की 20 से अधिक सड़क मार्गों का उद्घाटन तथा 271 किमी. लंबी 33 सड़कों का शिलान्यास किया किया।

दृष्टि The Vision

नोट :

मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले की यशिका खत्री ने विमान उड़ाने की प्रतियोगिता जीतकर अमेरिका की मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्राप्त की है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के एरिजोना के एम्ब्रीरिडल ऐयरोनोटिकल विश्वविद्यालय में यशिका खत्री के विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम आने से उनका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) की ओर से विश्व की उन 35 महिलाओं में शामिल हो गया है, जिन्हें मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्रदान की गई है।
- इस स्कॉलरशिप के लिये यशिका को 10 हज़ार डॉलर देकर सम्मानित करने के साथ ही एक साल तक एक विमान पर उसका नाम भी अंकित किया जाएगा। इस विमान पर भारत का तिरंगा भी एक साल तक फहराता रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि यशिका खत्री ने एरिजोना के एम्ब्रीरिडल ऐयरोनोटिकल विश्वविद्यालय से स्नातक की है तथा अब वह यूनिवर्सिटी ऑफ कोलेरेडो से एयरोस्पेस में पीएचडी कर रही है।
- विदित है कि मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अवार्ड होता है।

खेलो इंडिया प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले में आयोजित खेलो इंडिया नॉर्थ जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता में करनाल की रिद्धि फोर ने चार गोल्ड मेडल जीते है।

प्रमुख बिंदु

- सोनीपत में भारतीय तीरंदाजी संघ की और खेलो इंडिया के तहत नॉर्थ जोन की दूसरी प्रतियोगिता में 17 वर्षीय रिद्धि ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेटियों की शान बढ़ाई है।
- रिद्धि फोर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी एक गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार इन तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में उन्होंने कुल मिलाकर पाँच गोल्ड मेडल जीते हैं।
- उल्लेखनीय है कि रिद्धि फोर 6 इंटरनेशनल व 51 नेशनल मेडल हासिल करने वाली सीनियनर निशानेबाजी मुकाबलों में भी मेडल जीत चुकी है।

टैब वितरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पाँच ज़िलों के स्कूलों में टैब वितरित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाँच ज़िलों को चयन किया है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, अंबाला और करनाल शामिल हैं।
- पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में टैब वितरित किये जाएंगे तथा टैव के साथ दो जीबी डाटा भी मुफ्त मिलेगा।
- हालाँकि यह प्रोजेक्ट 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिये है, पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने अभी 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को ही टैब देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये सरकार 'पहल'नाम का सॉफ्टवेयर भी अपलोड करके देगी।

- उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हैं, इसलिये बाकी तीन ज़िलों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल बंद होने की वजह से राज्य के किन्हीं अन्य दो ज़िलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा।
- विदित है कि हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ की लागत से 5 लाख टैब खरीदने का टेंडर भी जारी किर दिया है।

एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में स्थित एसडीएस एजेंसी ने हिसार ज़िले में बनने वाले एलिवेटेड रोड को राज्य का अब तक का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- हिसार ज़िले में ट्रैफिक का बोझ कम करने हेतु शहर के बीचों-बीच एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
- एलिवेटेड रोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ताकि ज़्यादा-से-ज़्यादा वाहन इसका इस्तेमाल कर सकें।
- इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 8.9 कि.मी. तथा चौड़ाई करीब 15 मी. होगी।
- एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर 1100 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पानीपत ज़िले में बने एलिवेटेड रोड की लंबाई सर्वाधिक है, परंतु यह एनएचएआई के अंतर्गत आता है।
- बीएंडआर के अंतर्गत हिसार में बनाया जाने वाला यह एलिवेटेड रोड राज्य का एकमात्र सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को भी योजनाओं का लाभ देने के लिये ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ-साथ श्रमिकों की आय को भी डबल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिये राज्य में असंगठित मज़दूरों का पंजीकरण हो रहा है।
- पंजीकरण कराने वाले माल गोदाम श्रमिकों को भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- उन्होंने बताया कि श्रमिक समाज का असली निर्माता है। 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, तब उद्योगों के विकास में रेलवे का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। देश की तरक्की उद्योगों से, उद्योगों की तरक्की रेलवे से और रेलवे की तरक्की श्रमिकों से हुई। किसी भी देश की तरक्की श्रमिकों पर निर्भर करती है।
- हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन (निर्माण), प्रवासी मज़दूरों, दुकानदारों, मछुआरे व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों का भी पंजीकरण कर रही है। इनका पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर उन्हें स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोज़गार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

हरियाणा में स्कूल फीस वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में राज्य सरकार ने हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलने को नियंत्रित करने के लिये वार्षिक शुल्क वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसमें नए शुल्क मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और निजी स्कूलों की मान्यता वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त (निजी / गैर-सहायता प्राप्त) स्कूल हर साल अपने मौजूदा छात्रों के लिये शुल्क में वृद्धि कर सकता है, जो पिछले वर्ष के शिक्षण स्टाफ की मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति औसत प्रतिशत वृद्धि के बराबर है, लेकिन शुल्क वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत वृद्धि प्लस पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- इसके अलावा निजी स्कूल शैक्षणिक वर्ष के दौरान न तो शुल्क बढ़ाएंगे और न ही मुनाफाखोरी में लिप्त होंगे। हालाँकि, निजी स्कूल किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में किसी भी कक्षा में नए प्रवेश के इच्छुक नए छात्रों के लिये शुल्क का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा में करीब 8900 निजी स्कूल हैं। शिक्षा विभाग को विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान निजी स्कूलों द्वारा अभूतपूर्व शुल्क वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं। इसके बाद, हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2021 को निजी स्कूलों में फीस संरचना को विनियमित करने और निगरानी करने के लिये अधिसूचित किया गया।
- नए नियमों के तहत फीस को फीस और फंड के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो मान्यता प्राप्त स्कूल छात्र से वसूल करेगा।
- प्रवेश के समय, चाहे जिस ग्रेड या कक्षा में कोई छात्र स्कूल में प्रवेश कर रहा हो, स्कूल के अधिकारियों को अब माता-पिता या अभिभावक को उस वर्ष के लिये बारहवीं कक्षा तक की पूरी फीस संरचना का विवरण देना होगा, जैसा कि राज्य शिक्षा विभाग फॉर्म VI में घोषित किया गया है।
- प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्कूल के प्रबंधन के लिये शिक्षा विभाग को फॉर्म VI जमा करके प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं और अधिकतम सभी अनिवार्य शुल्क घटकों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर शुल्क एवं निधि नियामक समिति उल्लंघन के मामलों की जाँच करेगी और ऐसी जाँच तीन महीने से अधिक की अवधि में पूरी की जाएगी।
- यदि कोई स्कूल हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 158 (गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस और फंड से संबंधित) के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो इस तरह के पहले उल्लंघन के लिये फीस और फंड नियामक समिति को प्राथमिक स्तर तक के स्कूलों हेतु 30000 रुपए, मध्य स्तर तक के स्कूलों के लिये 50000 रुपए और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों के लिये 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने हेतु अधिकृत किया गया है।
- इसी तरह, इस तरह के दूसरे उल्लंघन के लिये मान्यताप्राप्त स्कूल पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो प्राथमिक स्तर के स्कूलों हेतु 60,000 रुपए; मध्य स्तर तक के स्कूलों के लिये 1 लाख रुपए और माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों के लिये 2 लाख रुपए तक हो सकता है ।
- इस तरह के तीसरे उल्लंघन के लिये, दूसरे उल्लंघन में लगाए गए दंड के अलावा, शुल्क और निधि नियामक समिति ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिये निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को सिफारिश कर सकती है। साथ ही ऐसे मामलों में निदेशक को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए अन्य प्रमुख प्रावधानों में, अब किसी भी छात्र को स्कूल द्वारा अनुशंसित दुकान से किताबें, कार्यपुस्तिका, स्टेशनरी, जूते, मोजे, वर्दी आदि खरीदने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई भी निजी स्कूल लगातार पाँच शैक्षणिक वर्षों से पहले अपनी वर्दी नहीं बदलेगा।
- नए नियमों में कहा गया है कि अब निजी स्कूलों द्वारा मासिक या द्वैमासिक या त्रैमासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा। कोई भी स्कूल छह मासिक या वार्षिक आधार पर फीस का संग्रह अनिवार्य नहीं करेगा।
- राज्य सरकार ने अनिवार्य शुल्क घटकों को भी परिभाषित किया है, जिसमें पंजीकरण के समय केवल एक बार देय होने के लिये विवरणिका और पंजीकरण शुल्क शामिल होगा; प्रवेश शुल्क स्कूल में नए प्रवेश के समय या कक्षा 1, 6वीं, 9वीं और 11वीं में प्रवेश के समय देय होगा; केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क होगा और सभी छात्रों द्वारा देय सभी सामान्य सुविधाओं के लिये समग्र शुल्क-एकल शीर्ष आवर्ती शुल्क होगा।

नोट :

- छात्रों से लिये जाने वाले वैकल्पिक शुल्क घटकों में परिवहन, बोर्डिंग, मेस या डाइनिंग, भ्रमण और इसी तरह की कोई अन्य गतिविधि शामिल होगी।
- नए नियमों के तहत, वार्षिक शुल्क वृद्धि का अनिवार्य मानदंड उन प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा जहाँ अनिवार्य शुल्क घटकों का कुल योग 12,000 रुपए प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है; मध्य, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहां अनिवार्य शुल्क घटकों का कुल योग 15,000 रुपए प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है।

'कचरे से कंचन' के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 10 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीवन को आसान बनाने के लिये आवश्यक 'स्वच्छता' पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राज्य में 'कचरे से कंचन' बनाने की प्रक्रिया पर कार्य शुरू करते हुए गुरुग्राम के सेक्टर-14 के नगर निगम कार्यालय तथा बंधवाड़ी में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बंधवाड़ी में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्लांट के स्थापित होने से गुरुग्राम दुनिया के सुंदर शहरों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में अग्रसर होगा।
- इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को ईकोग्रीन द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा निर्माण कार्य 2 साल में पूरा किये जाने की योजना है। इस 15 मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोज़ाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।
- ईकोग्रीन द्वारा प्लांट की क्षमता को 15 मेगावाट से बढ़ाकर 25 मेगावाट करने के लिये आवेदन किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। प्लांट की क्षमता बढ़ने से और अधिक कूड़े का निष्पादन किया जा सकेगा।
- गौरतलब है कि राज्य के सोनीपत ज़िले में भी 10 मेगावाट क्षमता के प्लांट द्वारा कचरे से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसके निर्माण में 117 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह भवन 2 एकड़ भूमि में तैयार किया जाएगा, जिसमें व्यापार भवन भी बनाया जाएगा। नगर निगम के 11 मंजिला भवन में 600 लोगों के बैठने की क्षमता का सभागार भी बनाए जाने की योजना है।
- केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के चालू होने के बाद दोनों शहरों (गुरुग्राम व फरीदाबाद) की कचरे की समस्या दूर होगी तथा लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा।

9वीं जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

- 12 दिसंबर, 2021 को हरियाणा राज्य के चरखी दादरी ज़िले के बाढड़ा क्षेत्र की खेल एकेडमी में संपन्न 9वीं जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में करनाल ज़िला और लड़कों के वर्ग में कुरुक्षेत्र ज़िले ने जीत दर्ज की।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रतियोगिता बाढड़ा क्षेत्र के गाँव चांदवास स्थित धूप सिंह खेल एकेडमी में आयोजित की गई थी।
- स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में करनाल ज़िले की टीम जींद ज़िले की टीम को हराकर विजेता बनी, जबकि लड़कों के वर्ग में कुरुक्षेत्र ज़िले की टीम ने फतेहाबाद ज़िले की टीम को हराकर जीत दर्ज की।
- इस प्रतियोगिता में चरखी दादरी व गुरुग्राम ज़िले की टीमें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।
- विजेता खिलाड़ियों को वॉलीबॉल संघ के राज्य महासचिव खूबेसिंह अरेला ने पुरस्कार प्रदान किया।

नोट :

मिस यूनिवर्स -2021

चर्चा में क्यों ?

- 13 दिसंबर, 2021 को इज़रायइल में आयोजित समारोह में 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने जीता।

प्रमुख बिंदु

- मिस यूनिवर्स का यह खिताब भारत को 21 साल बाद मिला है। इससे पहले यह खिताब भारत को वर्ष 1994 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने तथा वर्ष 2000 में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने दिलाया था।
- 21 वर्ष की हरनाज ने 75 देशों की खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं को पछाड़कर यह खिताब हासिल किया है।
- भारत के अलावा टॉप 3 में पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की महिलाएँ शामिल थीं।
- उल्लेखनीय है कि हरनाज संधू पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर-42 की छात्रा हैं। वह अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में मास्टर की डिग्री पूरी कर रही हैं। हालाँकि वह जज बनना चाहती थीं।
- हरनाज को अक्टूबर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का ताज पहनाया गया था। उन्होंने वर्ष 2017 में मिस चंडीगढ़ का तथा मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का खिताब भी जीता था।
- हरनाज संधू ने 2019 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था तथा ब्यूटी पीजेंट के टॉप 12 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थीं।

लीड्स रिपोर्ट: हरियाणा ने हासिल किया दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट में एक बड़ी छलांग लगाते हुए हरियाणा ने LEADS 2021 इंडेक्स में दूसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- सक्रिय नीतियों, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढाँचे और एक उत्तरदायी सरकार द्वारा संचालित सेवाओं ने हरियाणा को वर्ष 2019 इंडेक्स में अपने छठे स्थान की तुलना में चार स्थानों की वृद्धि प्राप्त करके लीड्स 2021 इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण और भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दिया है।
- हरियाणा द्वारा तैयार की गई रसद, भंडारण और खुदरा नीति-2019 राज्य के भीतर रसद पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिये उठाए गए सबसे महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक है।
- राज्य ने कई संकेतकों के लिये उच्चतम स्कोर हासिल किया है, जिनमें वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता, परिवहन के दौरान कार्गो डिलीवरी की समयबद्धता, परिचालन और नियामक वातावरण तथा नियामक सेवाओं की दक्षता शामिल हैं।
- इसके साथ ही, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में निजी माल ढुलाई टर्मिनलों की अधिकतम संख्या हरियाणा में है और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के मामले में हरियाणा नौवें स्थान पर है।
- राज्य वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स पार्कों और एकीकृत/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना के लिये 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।
- हरियाणा लॉजिस्टिक्स में कुशल जनशक्ति को सक्षम करने के लिये लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इकाइयों को श्रमिकों की प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी करता है।
- राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिये सिंगल डेस्क क्लीयरेंस मैकेनिज्म, सेल्फ सर्टिफिकेशन और भूमि अधिग्रहण में सहायता के माध्यम से नियामक व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है।

कृषि-उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार-2021

चर्चा में क्यों ?

- 18 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पशुपालन व मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास (हर हित स्टोर्स) में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिये 'कृषि-उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार-2021' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री रूपाला ने यह पुरस्कार हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल को डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी-सोलन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट-2021 के दौरान प्रदान दिया।
- हिमाचल प्रदेश ने मृदा स्वास्थ्य और कृषि विपणन और प्रथाओं में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिये पुरस्कार जीता, केसर संवर्धन और उत्पादन के लिये जम्मू और कश्मीर को सम्मानित किया गया, जबकि पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने पशु स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार जीता, जबकि उत्तराखंड को जैविक खेती के लिये पुरस्कार दिया गया।
- इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के तहत सम्मेलन में कुल 42 पुरस्कार वितरित किये गए जिसमें राज्य, शैक्षिक संगठन, कॉर्पोरेट कृषि और संबद्ध क्षेत्र, प्रगतिशील किसान, गांव, किसान उत्पादक संगठन, कृषि पत्रकारिता पुरस्कार (जागरूकता और समाधान-उन्मुख), सरकारी संगठन, पीएसयू, एकेडमी में उत्कृष्टता और कृषि भविष्य रत्न पुरस्कार शामिल रहे।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी-सोलन और सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (आईएमएफईडी) के संयुक्त तत्त्वावधान में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट-2021 का आयोजन किया गया।
- इस समिट का उद्देश्य कृषि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये रणनीतियाँ, किसान की आय को दोगुना करना, विचारों का एकत्रीकरण और बहुमूल्य अनुभवों को साझा करना था।

1 जनवरी से हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिये नो एंट्री

चर्चा में क्यों ?

- 22 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के गृह-सह-स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि वैक्सीन कवरेज को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी, 2022 से, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं मिली हैं, उन्हें भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जैसे- रेस्तरां, मॉल, बैंक, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिये टीमों का गठन करने का निर्देश दिया।
- आदेश के अनुसार 1 जनवरी, 2022 से रेस्टोरेंट, बार, होटल, अनाज मंडियों, विभागीय भवनों, शराब की दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थलों, राशन की दुकानों, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों, स्थानीय बाज़ार, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक, पार्क, जिम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा सार्वजनिक समारोहों के अन्य स्थानों में पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- इसके अलावा कॉलेजों/पॉलिटेक्निक के छात्रों (18 वर्ष से अधिक) के लिये कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से टीकाकरण के बिना सरकारी कार्यालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 93 प्रतिशत योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, जबकि 59 प्रतिशत को वैक्सीन की दोनों खुराक मिल गई हैं। वहीं गुरुग्राम में 100 प्रतिशत पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं।

नोट :

एचपीएससी, एचएसएससी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का निर्णय वापस लिया गया

चर्चा में क्यों?

- 22 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के निर्णय वापस लेने तथा विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिये एक समिति गठित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिये पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
- इस कमेटी में राज्यपाल (कुलपति) के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल किया जाएगा। समिति 15-20 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
- उन्होंने कहा कि एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों के संबंध में विश्वविद्यालयों को पहले भेजे गए पत्र को वापस ले लिया गया है।
- मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यूजीसी के निर्देशों का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से और योग्यता के आधार पर ही की जाएंगी। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तर्ज़ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये डीए की दरों को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे राज्य के खजाने पर सालाना 672 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये नई पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार की तर्ज़ पर 1 जनवरी, 2022 से नियोक्ता के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा भी की। इस फैसले के लागू होने से कर्मचारियों को 25 करोड़ रुपए मासिक और 300 करोड़ रुपए सालाना का लाभ मिलेगा।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी घोषणा की कि सदन में एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसके तहत शून्यकाल में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का लिखित जवाब राज्य सरकार द्वारा संबंधित विधायक को एक महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' हरियाणा में लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेबिनार के माध्यम से 'सेवा इंटरनेशनल' नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' को हरियाणा में लॉन्च किया। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 079690700500 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से नि:शुल्क परामर्श ले सकता है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था। यही नहीं कोविड के बाद भी मरीज़ों को सहायता दी गई।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब 300 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सीएसआर ट्रस्ट का गठन किया है ताकि सीएसआर के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके।
- गौरतलब है कि 'सेवा इंटरनेशनल' द्वारा विश्व के 26 देशों में समाजसेवा का कार्य किया जा रहा है। उक्त फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 'साथ' भारत में चार राज्यों में चलाई जा रही है।

नोट :

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- 25 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य स्तरीय सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कौशल रोज़गार निगम का पोर्टल लॉन्च किया व व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष-2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अनेक घोषणाएँ भी की।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि वर्ष-2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी प्रकार, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली डायल-112 को मूक-बधिर दिव्यांगजन के लिये सुगम बनाया जाएगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनकी समस्या को साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के माध्यम से समझकर उन्हें तुरंत पुलिस सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिये रोहतक और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर सभी ज़िलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आर्म्स लाइसेंस को सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया जाएगा, न कि प्रतिष्ठा के लिये।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जन-वितरण प्रणाली को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ दिया गया है। जनवरी-2022 से राशन डिपो पर राशनकार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि परिवार पहचान-पत्र से ही राशन मिलना संभव होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या जुड़ने या घटने का हिसाब भी परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से होगा।
- परिवार पहचान-पत्र के साथ जन्म-मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और भविष्य में विवाह पंजीकरण को भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा।
- उन्होंने इस अवसर पर गुरुग्राम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाने की घोषणा की। इस पार्क में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

सुशासन सूचकांक, 2021 में हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप 'ए' में हरियाणा को चतुर्थ रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं गुजरात को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- हरियाणा ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 5.327 स्कोर के साथ ग्रुप 'ए' में चतुर्थ रैंक प्राप्त की है।
- हरियाणा के पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में इस वर्ष के स्कोर में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछली बार इसका स्कोर 5.00 था, जो अब बढ़कर 5.33 हो गया है।
- हरियाणा ने मूलत: कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र, आर्थिक शासन क्षेत्र तथा समाज कल्याण एवं विकास क्षेत्र में सुधार किया है।

नोट :

- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें हरियाणा की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	हरियाणा की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	द्वितीय	0.507
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	चतुर्थ	0.657
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	द्वितीय	0.696
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	10वीं	0.431
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	तृतीय	0.791
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	6वीं	0.570
7. समाज कल्याण एवं विकास	10वीं	0.392
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	9वीं	0.213
9. पर्यावरण क्षेत्र	9वीं	0.153
10. नागरिक केंद्रित शासन	प्रथम	0.914

मुख्यमंत्री ने किया एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल ज़िला के तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब साढ़े 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियाँ लंबे तक स्टोर की जा सकेंगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैक हाउस में सब्जियों की धुलाई, छँटाई, सफाई, पैकिंग तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, जिससे सब्जियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। इससे किसानों के साथ-साथ खेतों में काम करने वाले मज़दूरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
- तरावड़ी के इस पैक हाउस के निर्माण से 272 किसानों के समूह 'किसान उत्पाद संघ' द्वारा करीब 600-700 एकड़ में उगाई जाने वाली सब्जियों की स्टोरेज में सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाउस महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- प्रदेश का यह 7वाँ पैक हाउस है, जिसके लिये सरकार ने साढ़े 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये भी इस प्रकार के ऋण दिये जा रहे हैं, जिन पर भारी सब्सिडी दी जाती है।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के 50 और पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य के किसानों को इस तरह के पैक हाउस बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये 70 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें और अधिक सशक्त होने में सहायता मिलती है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिस पर किसान स्वयं को पंजीकृत कर लाभ उठा सकते हैं।

अंबाला के नग्गल में होगी उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की ब्रांच की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

- 26 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला के नग्गल में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की ब्रांच की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत में यह अपनी तरह की पहली ब्रांच होगी, जहाँ कई गंभीर, नए रोग एवं वायरस की जाँच और उनके आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसकी स्थापना के लिये 2.03 करोड़ रुपए की लागत से ज़मीन की रजिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी गई है और अब भविष्य में एनसीडीसी ब्रांच की स्थापना का कार्य तेज़ी से हो सकेगा।
- उन्होंने कहा कि यह आधुनिक उपकरणों से लैस अत्याधुनिक लैब होगी, जिसमें नई बीमारियों की पहचान, उनके विश्लेषण एवं रोकथाम के तरीकों पर कार्य किया जा सकेगा। नीपा वायरस, जीका वायरस, रेबीज, जूनाटिक रोग, कोविड-19, ओमीक्रॉन, हेपेटाइटिस के अलावा अन्य गंभीर वायरस की जाँच और सभी प्रकार के नए टेस्ट यहाँ इस लैब में हो पाएंगे।
- उन्होंने बताया कि यह अपने आप में एक अलग ब्रांच होगी और इसकी स्थापना में राज्य व केंद्र सरकार की संयुक्त तौर पर भूमिका है। एनसीडीसी में एकीकृत रोग निगरानी व शोध कार्यों को बढ़ावा, पर्यावरणीय बदलाव पर अध्ययन, प्रयोगशाला में गुणवत्ता एवं क्षमता का निर्माण इत्यादि गतिविधियों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा।
- यह केंद्र विभिन्न वैक्सीन, दवाइयों व अन्य नैदानिक किट की उपलब्धता के लिये कार्य करेगा। महामारी वैज्ञानिकों, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों व प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिये एक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर भी इसे विकसित किया जाएगा। यहाँ पर एनसीडीसी की देखरेख स्टाफ एवं अन्य कई नियुक्तियाँ भी की जाएंगी, ताकि कार्य बेहतर प्रकार से हो सके।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली की जॉइंट डायरेक्टर डा. शिखा वरधान और अंबाला के सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि तीन चरणों में एनसीडीसी ब्रांच का निर्माण पूरा किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण में बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके बाद तीसरे चरण में लैब की स्थापना होगी।
- यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिनमें बॉयो सेफ्टी केबिनेट, इन्क्यूबेटर, नॉन रेफ्रिजरेट सेंट्रीफ्यूज, कोल्ड सेंट्रीफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर मशीन, ड्राइ ब्लॉक इनक्यूबेटर, रेफ्रिजरेटर, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, डीप फ्रीजर, ट्रेनिंग माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप कम्पाउंड, एलीसा रीडर विद वॉशर, माइक्रोपिपटीस्ट ऑफ ऑल साइज, मिली-क्यू वॉटर प्योरीफायर एवं अन्य उपकरण होंगे।
- महामारी विज्ञान के साथ राज्य निगरानी इकाई, आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी), बीएसएल 2 सुविधा के साथ माइक्रोबायोलॉजी (वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जूनोटिक रोगजनकों और परजीवी विज्ञान) और कीट विज्ञान आदि की जाँच होगी।

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में हरियाणा 11वें स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।

नोट :

- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में हरियाणा 49.26 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 11वें स्थान पर है। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले, तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

कृषि विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग में एचएयू लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम

चर्चा में क्यों?

- 29 दिसंबर, 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड एचीवमेंट्स में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- देश भर में अटल रैंकिंग योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। गत वर्ष 2020 में भी विश्वविद्यालय ने प्रथम रैंक हासिल की थी, लेकिन उस समय केवल 674 शिक्षण संस्थानों ने ही आवेदन किया था। इस बार देश भर से 1438 विश्वविद्यालयों और संस्थानों सहित सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएस आदि ने हिस्सा लिया।
- विश्वविद्यालय ने सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर मंर चौथा स्थान हासिल किया है।
- अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड एचीवमेंट्स का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है। इसमें कई सूचकों के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को रैंकिंग दी जाती है। विश्वविद्यालय को बौद्धिक संपदा अधिकार, इनोवेशन, स्टार्ट-अप तथा उद्यमिता के कार्यक्रम व गतिविधियाँ, आई एंड ई को स्पोर्ट करने के लिये प्री-इनक्यूबेशन एंड इनक्यूबेशन ढाँचा तथा सुविधाओं तथा आई एंड ई गतिविधियों को स्पोर्ट करने व प्रोत्साहित करना शामिल है।
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्थापित एबिक सेंटर उत्तर भारत का पहला और भारतवर्ष का दूसरा केंद्र है, जो इनोवेशन, स्टार्टअप्स व उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। विदित है कि एबिक सेंटर को हाल ही में देशभर में सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेशन सेंटर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया नववर्ष का तोहफा

चर्चा में क्यों?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर को नववर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर, 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर एक लाख रुपए तथा हेल्पर को 50 हज़ार रुपए की राशि दिये जाने की घोषणा की।
- इसके साथ ही, मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने और दो साल (वर्ष 2019-20 और 2020-21) का एरियर देने तथा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिये सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1000-1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की।

नोट :

- उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। बल्कि प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ-साथ क्रैच खोला जाएगा। इन क्रैच में बच्चों के लिये और भी बेहतर सुविधाएँ होंगी। इन क्रैच में भर्ती के लिये नए उम्मीदवारों के साथ-साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा।
- आंगनबाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 12 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी को आधुनिक बनाने और बच्चों के लिये बेहतर सुविधाएँ शुरू करने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा ताकि वे पोषण ट्रैकर एप पर अपनी आंगनबाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें। इसके लिये आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।

दृष्टि The Vision

नोट :